**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्य सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2159

उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

**जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधान मंत्री की छात्रवृत्ति योजना हेतु आवंटन**

**2159. श्री नज़ीर अहमद लवायः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) हेतु निधि आबंटन में वृद्धि करने की कोई योजना है;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई की है; और
(घ) इस योजना से अब तक लाभान्वित होने वाले छात्रों की सूची क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (घ): जी, नहीं। योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में योजना की मॉनीटरिंग और सुचारू कार्यान्वयन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गई है। आज की तारीख तक अंतर-मंत्रालयी समिति की 17 बैठकें हो चुकी हैं।

- जम्मू और कश्मीर सरकार योजना के कार्यान्वयन से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है।

- योजना का कार्यान्वयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को सौंपा गया है।

- एआईसीटीई द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एक वेबपोर्टल बनाया गया है और विद्यार्थियों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

- जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार, शैक्षिक वर्ष 2014-15 से, सुविधा केन्द्र के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने और उनके दस्तावेज सत्यापित करने के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है।

- केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार किया गया है जिन्होंने केन्द्रीयकृत परामर्श के माध्यम से आवंटित कालेजों/संस्थान में प्रवेश लिया है या यूजीसी अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत या एआईसीटीई या किसी अन्य विनियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त कालेजों में अपने स्वयं के स्तर पर प्रवेश लिया हो। उन विद्यार्थियों, जिन्हें अभी तक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है, सूची http://www.aicte-india.org/renewal.php पर दी गई है।

*****